

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 अप्रैल, 2023 चैत्र 22, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 11/2023/320/94-स्टा0नि0-2–2023 लखनऊ, 12 अप्रैल, 2023

> अधिसूचना आदेश

पоआо−240

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ नई इकाई/पार्क की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर-12.2, 13.2, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छुट प्रदान करती है:

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा	प्रयोजन	छूट की	लिखत की प्रकृति
नीति, 2022 का प्रस्तर		सीमा	
1	2	3	4
12.2	नीति के अधीन राज्य में कहीं भी सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करने अथवा पट्टा पर लेने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर

	I	_	
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा	प्रयोजन	छूट की	लिखत की प्रकृति
नीति, 2022 का प्रस्तर		सीमा	
1	2	3	4
13.2	नीति के अधीन राज्य में	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
	कहीं भी सौर ऊर्जा		1899 की अनुसूची 1(ख) के
	परियोजना / सौर ऊर्जा पार्क की		अनुच्छेद 23 के खण्ड(क) के
	स्थापना हेतु भूमि क्रय करने		अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद
	अथवा उसे पट्टा पर लेने पर		35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.10.1	5 MW से अधिक की	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
	धारिता (Capacity) वाले		1899 की अनुसूची 1(ख) के
	स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा		अनुच्छेद 23 के खण्ड(क) के
	परियोजना हेतु भूमि के क्रय		अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद
	अथवा पट्टा पर लेने पर		35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.10.2	सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता को	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
	भूमि क्रय करने अथवा उसे		1899 की अनुसूची 1(ख) के
	पट्टा पर लेने पर		अनुच्छेद 23 के खण्ड(क) के
			अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद
			35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.10.3	5 MW से कम की धारिता	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
	(Capacity) वाले स्टैण्ड		1899 की अनुसूची 1(ख) के
	अलोन सौर ऊर्जा परियोजना		अनुच्छेद 23 के खण्ड(क) के
	हेतु भूमि क्रय करने अथवा		अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद
	उसे पट्टा पर लेने पर		35 के अधीन पट्टा के लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्निलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2-यू0पी0एन0ई0डी0ए0 के पक्ष में स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय निबंधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की अविध परियोजना पूर्ण करने हेतु नीति में यथाविहित अविध से कम अविध नहीं होनी चाहिए।

3-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

> आज्ञा से, लीना जौहरी, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11/2023/320/XCIV-S.R.-2-2023 dated April 12, 2023:

No. 11/2023/320/XCIV-S.R.-2-2023 Dated Lucknow, April 12, 2023

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act ,1899 (Act no. 2 of 1899) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this notification in the *Gazette*, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit/Park under the Uttar Pradesh Solar Energy Policy,2022, in accordance with the Para 12.2, 13.2, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3 of the aforesaid Policy for the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column-3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column-4:-

Para of Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
	On purchasing private land or taking it on lease for setting up solar energy unit anywhere in the state under the policy	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
	On purchasing land or taking it on lease for establishment of solar power project/solar park anywhere in the state under the policy	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
	On purchase or lease of land for a stand alone solar power project with a capacity of more than 5 MW	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
	On purchase or lease of land to Solar Park Developer	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
	On purchase or lease of land for stand alone solar power project with capacity less than 5 MW	100%	On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:-

- 1. The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2022 and also signs as a witness for the said purpose.
- 2. Irrrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the UPNEDA shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee shall not be less than the period, as prescribed in the policy, for the completion of project.
- 3. The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

By order, LEENA JOHRI, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० २३७ राजपत्र—२०२३—(२८४)—599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १० सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन—२०२३—(२८५)—१५० प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।